Shri Nath Pai: May we know if he can assure us that no cease-fire agreement will be made with the aggressor which will involve giving away even an inch of our territory, which will depart from the solemn resolve of the House? What is preventing him from giving that assurance? It means that something wrong is happening. Why is he hesitating to give that assurance? It is not only the Opposition which is wanting, Congressmen are as much interested in it.

Shri C. Subramaniam: We will take care of the Congressmen.

Shri Kamalnayan Bajaj (Wardha): This matter is very serious and urgent, and I also share the anxiety and the distress of the other Members here, but I feel that it is not for the House to demand to know whatever the Government is doing. If the leaders of the Opposition are taken into confidence that should suffice. Otherwise in such a serious matter, if the Lok Sabha is to be taken into confidende, if the public is to taken into confidence, to carry on the defence of the country, it cannot be done, it should not be done, according to me. Of course, I share the anxiety and distress, but we should not be excited about it. I agree that the Opposition has a right, and that some of their leaders should be taken into confidence, and they should be informed of what is going on.

Mr. Deputy-Speaker: Shri Subramaniam will convey the feelings of the hon. Members to the Prime Minister.

Shri Ranga: What is it you are conveying? Here is a member of the Cabinet who has received a message from the Prime Minister saying that no statement is going to be made. You have heard what some of our Members have already stated. We want the Prime Minister as well as this Government to clearly understand one thing, that the leaders of their party appart, the leaders of the Opposition have a right to be consulted before any final decision is taken by this Government, whatever may be that decision. They should be consulted, and their advice should be given proper weight in their Cabinet counsels and thereafter alone they should reach decisions and then implement them. I do not know what they are going to do between now and tomorrow morning,—

श्री ओंकार लाल बेरवा : यह तमाम देश का सवाल है । ऐसा कोई काम आप न करें जिस से आप देश में मुंह दिखाने के काबिल न रहें ।

Shri Ranga: —but, if anything is sought to be done between now and tomorrow morning when the House meets, then, I would like the hon. Minister who is present here to convey to the Prime Minister our wish that he should take expeditious steps to send for us and then consult us and afterwards take their own decision.

Mr. Deputy-Speaker: Shri K. N. Tiwary. Does the House like to sit beyond 7 O'clock, or till 7.30?

Shri Yashpal Singh: 7.30.

Mr. Deputy-Speaker: All right.

Shri Brij Raj Singh-Kotah (Jhalawar): We have been sitting here from this morning.

18.51 hrs.

DEMANDS FOR GRANTS—*contd.*

MINISTRY OF FOOD AND AGRICULTURE—*contd.*

श्री क० ना० तिवारी : उपाध्यक्ष महोदय, में फुड एंड एग्रिकलचर मिनिस्ट्री की गिमांड्ज को स्पोर्ट करता हूं । साथ ही मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं कि अब तक हिन्दुस्तान की एग्रीकलचरल पालिसी में जो बात नहीं हुई वह इन्हों ने की है । इन्होंने प्राइस फिक्सेशन को अमल में लाया है, चाहे वह टैम्पोरेरी ही हो । उस का नतीजा यह हुआ है कि जो भाव

गिर जाया करते थे वे भाव इस साल नहीं गिरे बल्कि अन्न के भाव बराबर ऊंचे रहे हैं।

बहुत सी बातों में जाना मैं नहीं चाहता हूं। दो एक सुझाव ही मैं मंत्री महोदय के सामने रखना चाहता हूं। आज उत्पादन बढ़ाने का सवाल हमारे सामने है। कृषि का सम्बन्ध लोगों से आज से या पचास सौ बरस से नहीं है, वह बहुत पुराना है किसान को आप के शहर वालों के लिये डिवेलेपिंग इंडस्ट्री के लिए, फौज के लिए, और तमाम उन लोगों के लिए जिनके पास जमीन नहीं है जो खेती नहीं करते हैं, जो उत्पादन नहीं करते हैं, अन्न पैदा कर के देना होता है। अन्न तथा दूसरी चीजें जो देश के लिए आवश्यक हैं, वह किसान को देनी पड़ती हैं। इतना ही नहीं, विदेशी मुद्रा जितनी हम इंडस्ट्री वगैरह से कमाते हैं उस का आधा हम एग्रिकलचर से कमाते हैं, फिर चाहे वह ज्यूट हो, शूगर हो, कैशूनट हो या कोई दूसरी चीज हो। इसलिए किसान पर कितनी बड़ी रिसपांसिबिलिटी है इस को आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं।

अभी यहां का पापुलेशन 2.5 बढ़ रहा है और उसके साथ साथ हमारा एग्रीकलचर जो है वह तीन प्वाइंट बढ़ रहा है। इसके बारे में लोगों के दो मत हैं। एक मत तो यह है कि एग्रीकलचर से जितनी पैदावार आज हो रही है उससे ज्यादा नहीं होगी। दूसरा मत है कि इस से ज्यादा पैदावार हो सकती है मैं इसको आपके सामने पढ़ देता हूं :-

"....it is interesting to note the controversy as to whether agricultural production in India can at all increase as envisaged in the Five Year Plans. Prof. Arthuer Lewis for instance in his model of Indian Economic Growth (1955) assumed that even with the best of effort, food output in India can be raised only by a total of about 45 per cent in the 25 years between 1955 and 1980. A 45 per cent increase in populatcion and 118 per cent increase in national income during the same period will however need an increase of 90 per cent in the volume of food supply as it was in 1955."

आग चल कर उनसे डिफर करता है फोर्ड फाउंडशन जो कहता है :

"But the Ford Foundation which inquired into the possibilities of increased food production in India holds a different opinion. According to them the average performance in productivity is low compared with other advanced countries of the world though the best in Indian agriculture compares very favourably with the best elsewhere."

उसके लिए जरूरत है जो हम लोग बारबार कहते हैं :

"The team therefore felt that pushing up the low performance to the high levels attained by some Indian farmers would not be difficult of achievement, provided better techniques and implements were made available along with the intensive use of good seeds, manures and irrigation and these suggestions are already being carried out in selected areas and the results of the full implementation of this programme are awaited with interest..."

बराबर यह कहा गया है कि हमारे यहां पर इन सब चीजों को उपलब्ध करने की जरूरत है। पानी और खाद की सब की जरूरत है। गवर्नमेंट आफ इंडिया की जितनी पबलिकेशंज आती हैं उन सब में ये बातें कहीं जाती हैं लेकिन डिफिकल्टी यह है कि लोएस्ट लेवल तक जाते जाते इनका इम्प्लेमेंटेशन नहीं हो पाता है। इसके दो कारण है। एक कारण यह है कि सामुदायिक विकास का जो विभाग है उसके हाथ में इसका इम्प्लेमेंटेशन है और जहां तक पालिसी का सवाल है, उसको बनाना एग्रीकलचर मिनिस्ट्री के हाथ में है। इसलिए मेरा सुझाव है कि

[श्री क० ना० तिवारी]

सेंट्रल गवर्नमेंट जो शंकर कमेटी मुकर्रर की थी उसकी जो रिपोर्ट थी, उसका इम्प्लेमेंटेशन होना चाहिये ।

दूसरा सुझाव मेरा यह है कि एक सेंट्रल पालिसी होनी चाहिये । जब कोई सवाल हम लोग करते हैं तो कह दिया जाता है कि यह प्राविंशल मैटर है और जब प्राविंशल मैटर वह हो जाता है तो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वह लाचार हो जाती है । इस लिए सेंट्रल पालिसी एक होनी चाहिये । सेंट्रल सर्विस इसकी होनी चाहिये ताकि फूड के प्रोडक्शन के मामले में किसी तरह की कोई बाधा न पड़े ।

अब मैं जोंज के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं । जब जोंज को समाप्त करने की मांग की जाती है और कहा जाता है कि जोनल रेस्ट्रिकशंज को हटा दिया जाय तो कहा जाता है कि हम को बफर स्टाक करना है । हमें गेहूं दो मिलियन टन अधिक मिलने जा रहा है । दो मिलियन टन राइस हम को ज्यादा मिला है । इसी तरह से लास्ट यीअर के प्रोडक्शन से चार मिलयिन टन अनाज ज्यादा पैदा होने की सम्भावना है । पी० एल० 480 में भी आप इम्पोर्ट करने जा रहे हैं । जब आप बफर स्टाक बनाना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूं । पर एकड़ के पीछे ग्रेडिड लेवी अगर लगा दी जाए तो जो मकसद आपका है वह भी पूरा हो सकता है और जोंज को भी समाप्त किया जा सकता है । इससे कंट्री का इंटेग्रशन बहुत खतरे में पड़ गया है । महा-राष्ट्र, बम्बई, तथा दूसरे स्थानों के लोगों की हालत यह हो गई है कि कोर्स ग्रेंज पर भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है, पल्सेज के ऊपर भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि रेस्ट्रिकशंज न हो तो भी वे लगा देती हैं । इस वास्ते जब तक कोई सेंट्रल पालिसी नहीं होगी तब तक यह बीमारी दूर नहीं होगी । एक पार्ट के लोग दूसरे पार्ट से अच्छी तरह से खायें और दूसरे हिस्से के लोग तकलीफ़ में रहे, यह चीज चलने वाली नहीं है । दूसरा इसका रिजल्ट यह होगा कि जब रेस्ट्रिकशंज रहेगी तो जहां सरपलस है वहां के किसानों को कम दाम मिलेंगे । कल मैंने सुना था एक पंजाब के एम० पी० को कहते हुए कि जो आपने प्राइस फिक्स की है उससे चौदह रुपये फी क्विंटल भाव गिर गया है फिर भी आपके पास वहां कोई ऐसी मशीनरी नहीं है कि आप उसको खरीद कर सकें ।। इसलिए मेरा सुझाव है कि जोनल सिस्टम को आप जल्दी से जल्दी हटा दें ।

कंट्रोल का भी सवाल है । प्राइस फिक्सेशन के लिए कोई साइंटिफिक बेसिस आज पक नहीं निकाला गया है । यहां तक कि शूगर केन तक के लिए इतने बरस हो गए हैं फिर भी आपके यहां कोई मैथड नहीं है । मेरा सुझाव है कि आप जिस तरह से लेबर के लिए कास्ट आफ प्रोडकशन फिगर्ज निकालते हैं और उसके लिए जो मशीनरी है वैसी ही मशीनरी आपकी यहां भी होनी चाहिये जिससे कि कास्ट आफ प्रोडकशन जिले के स्तर से लेकर प्राविंस के स्तर तक निकाली जा सके ।

शक्कर के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं । इस साल शक्कर का उत्पादन 31 लाख टन होने का अनुमान लगाया गया है जो कि पिछले साल से पांच लाख टन के करीब अधिक है । इंटरनल कंजम्पशन आपकी 26 लाख टन होगी । करीब चार पांच लाख टन आप के पास चीनी बच जाएगी । इसको आपको एक्सपोर्ट करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा फारेन एक्सचेंज कमानी चाहिये ।

लास्ट यीअर शूगर का जितना प्रोडकशन हुआ था उस पर बैंक्स ने 70 से 75 परसेंट तक एडवांस दिया था । यह कंट्रोल्ड कमोडिटी है । जब बैंक एडवांस करते हैं तब उसमें से मिल वाले ग्रोअर्ज को पैसे देते हैं । जब एड-वांस नहीं मिलता है तो ग्रोअर्ज जो केन सप्लाई करते हैं, उनका पैसा भी रुक जाता है । मेरा निवेदन यह है कि जो आपका पांच लाख टन

ज्यादा प्रोडकशन हुआ है उस पर भी उसी हिसाब से पैसा बैंकों को देना चाहिये ताकि ग्रोअर्ज़ को मिल वाले पैसे दे सकें ।

जो पुरानी मशीनें हैं जैसे ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में हैं, नार्थ बिहार में है तथा दूसरी जगहों में हैं, उनके बारे में आपकी पालिसी यह है कि इनको एक्सटेंशन वगैरह सब दिया जाए । लेकिन डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं कि कहीं फाइनेन्स में जाकर मामला रूक जाता है, कहीं कोई और कमी रह जाती है । इसलिये मेरा निवेदन है कि कहीं मामला रुके नहीं । उन को टाइम लगता है । जो सुविधा मिलनी चाहिये वह मिले जिस में समय से वह लोग अपना एक्सटेंशन कर सकें और शूगर को अच्छी तरह से तैयार कर सकें । अगर ऐसा नहीं होता तो ग्रोग्रर्स को बड़ी तकलीफ होती है । अगर यह एक्सटेंशन नहीं हुआ तो गन्ना खेतो में पड़ा रह जायेगा ।

19 hrs.

श्रीमती गंगा देवी (मोहनलालगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी प्रतीक्षा के बाद मुझे बोलने का समय मिला है, इसके लिये मैं आपका धन्यवाद करती हूं ।

खाद्य समस्या कोई नई समस्या नहीं है । है । स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद देश को बराबर इसका सामना करना पड़ रहा है और तब से अभी तक खाद्यान्नों की कीमतें बराबर बढ़ती जा रही हैं । किन्तु सन् 1963-64 में जो समस्या उत्पन्न हो गई थी और जिस प्रकार के दृश्य हमारे सामने देखने में आये उनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी । फिर भी हमारे खाद्य मन्त्री ने बड़े परिश्रम और लगन के साथ देश में फैली उस अशान्ति को किसी हद तक शान्त किया है । इसके लिये मैं उनका धन्यवाद करती हूं । किन्तु चारों ओर से जो भुखमरी के समाचार आ रहे हैं उनको समाप्त करने का कोई उपाय अभी तक नहीं हुआ है ।

भारत एक विशाल देश है और इसका इतिहास बतलाता है कि यह एक कृषि प्रधान देश रहा है । प्रत्येक खाद्य पदार्थ इस देश में उत्पन्न होता है । अन्न से लेकर फल, तथा जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं सभी देश के किसी न किसी कोने में पाये जाते हैं । देश के बटवारे के बाद देश की खाद्य समस्या पर बड़ा खराब प्रभाव पड़ा । पंचवर्षीय योजना की स्कीम रक्खी गई । लोगों को बड़ी आशा हुई कि पहली व दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं का समय निर्धारित होने से हमारी खाद्य समस्या आसानी से हल हो जायेगी । पहली पंचवर्षीय योजना में 361 करोड़ रु० जो कि प्रथम योजना की निर्धारित धन राशि का 17.4 प्रतिशत था, कृषि तथा खाद्य की उत्पत्ति में लगाया गया । इसके साथ 561 करोड़ रु० सिंचाई की स्कीमों में लगाया गया । अन्य विभागों से अधिक पैसा खाद्य तथा कृषि में लगाने का निश्चय सरकार कर रहा है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में 20 प्रतिशत रुपया कृषि तथा सिंचाई पर लगाया गया । इसी प्रकार 1718 करोड़ रु० जो पूरी योजना का 25 प्रतिशत है कृषि और खाद्य मन्त्रालय की तीसरी योजना पर लगाया गया । काफी पैसा इस ओर खर्च किया गया है किन्तु फिर भी उत्पत्ति में कुछ अधिक प्रगति दिखाई नहीं पड़ती । दिन पर दिन खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं ।

खाद्य समस्या को हल करने में सरकार ने विशेष दिलचस्पी और परिश्रम से काम किया किन्तु सरकार ने कृषि फसलों की कोई सही प्लैनिंग नहीं की है । इसी कारण इस विभाग पर सबसे अधिक पैसा भी खर्च हो रहा है किन्तु फिर भी कोई प्रगति नहीं हो रही है । आफिसर पर आफिसर बढ़ा दिये गये, दफ्तर बढ़ा दिये गये किन्तु सब कागजी काम बढ़ रहा है । यदि प्लैनिंग सही होती तो जो रुपये हम नए नए आफिस खोलने में, एग्रीकल्चर आफिसर, डायरेक्टर्स आदि की सैलरीज में खर्च करते हैं वह धन किसान को खाद, बीज सिंचाई आदि साधन देने में खर्च कर सकते । यदि हम ऐसा करें तो किसान अपना कार्य अच्छी तरह करेगा

[श्रीमती गंगा देवी]

श्रौर श्रधिक से श्रधिक श्रन्न की पैदावार करके देगा ।

हमने बड़े बड़े डैम बनाये, लाखों करोड़ों रुपये उनमें लगाये श्रौर लगाते चले जा रहे हैं । किन्तु किसान को उन से कोई लाभ नहीं । इतने रुपयों से यदि गांव गांव में ट्यूबवैल लगा दिये जाते तो किसान की पानी वाली परेशानी दूर होती श्रौर दुगुनी श्रौर चौगुनी फसल वह पैदा कर सकता था । श्राज भी यदि सरकार इस प्रकार का प्लान न बना पाई जिससे देश का प्रत्येक व्यक्ति दो समय भरपेट खाना खा सके, तो उसके सारे प्लान बेकार हैं ।

श्राज देश चारों श्रोर से शत्रुश्रों से घिरा हुश्रा है । हम बाहरी देशों से श्रन्न मंगाते हैं । उस पर देश निर्भर कर रहा है । यदि यह सब बाहरी खाद्य सामग्री श्राना बन्द हो जाये तो क्या परिस्थिति हमारी होगी यह एक गम्भीर प्रश्न हमारे सामने है । इस कारण मेरा सरकार से नम्र निवेदन है कि श्रन्य दूसरे सभी प्रोजैक्ट्स में श्रधिक धन न लगा कर कृषि इण्डस्ट्री पर पूरी ताकत लगायें, जिसकी इस समय श्रति श्रावश्यकता है । जिससे हमारा देश खाद्य समस्या में श्रात्म निर्भर हो सके । दूसरी श्रौर तीसरी पंचवर्षीय योजनायें भी समाप्त हो गईं हैं किन्तु हम श्रपने निर्धारित लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाये । तीसरी योजना के श्रन्त तक कृषि उत्पादन 105 मिलियन टन हो जायेगा, यह निश्चय था, पर श्रांकड़ों से पता चलता है कि कृषि उत्पादन 90 मिलियन टन हो पाया है । यह उत्पादन लक्ष्य से काफी कम है । लक्ष्यपूर्ति नहीं हो पाई । जरूरत से ज्यादा पैसा भी खर्च हो रहा है श्रौर फिर भी उत्पादन जरूरत से काफी कम हो रहा है ।

उत्पादन श्रपने लक्ष्य तक न पहुंचने के कई कारण हैं । सबसे पहला कारण जमीन उन लोगों को न मिलना, जो वास्तव में किसान नहीं हैं श्रर्थात् जो स्वयं खून पसीना बहा कर काश्त करता है जमीन उसको नहीं मिली । जमींदारी उन्मलन के बाद बड़ी बड़ी जोत की जमीनें श्रौर बंजर जमीनें भी उन लोगों को दी गई, जो बड़ी पूंजी वाले हैं । जो ट्रैक्टर खरीद कर श्रपनी जमीनें जुतवाते हैं । जो कल जमींदार थे, वे श्राज बड़े बड़े फार्मों के मालिक बन गये हैं । हम समाजवाद की बात केवल कहते हैं, किन्तु उस पर श्रमल नहीं करते हैं । बड़े फार्म वाले जो उत्पादन करते हैं वह स्टोर में जमा हो जाता है । वह बाजार में नहीं जाता । या तो वह ब्लैक से बिकता है या बाजार में उस वक्त जाता है जब कीमतें खूब चढ़ जाती हैं । वे लोग तो इसी इन्तजार में रहते हैं कि कब मूल्य बढ़ें श्रौर कब वे गल्ला बेचें । इस प्रकार के समाज विरोधी तत्वों के कारण कई स्थानों पर गल्ले पर लूटमार मची । मेरा सरकार से निवेदन है कि इस प्रकार के एण्टी सोशल एलीमेंट्स को समाप्त करने के लिये उसे कोई सख्त कदम शीघ्र उठाना चाहिये । क्योंकि व्यापारी श्रौर बड़े स्तर का प्रोड्यूसर्स होंडिंग श्रौर ब्लैक करने में लगे हुए हैं । उन्हें पैसा चाहिये भले ही गरीब श्रादमी भूखों मर जाये । यदि सरकार कानूनी तरीके से शीघ्र ही इस प्रकार के एलिमेंट्स को समाप्त नहीं करेगी तो इस प्रकार के एजिटेशन बराबर होते रहेंगे ।

यदि हम खेतिहर मजदूरों व भूमिहीन किसानों को जमीन दे देते तो देश को श्रात्म निर्भर होने में बड़ी सहायता मिलती । श्राज भी देश में बहुत बड़ी जमीन ऐसी पड़ी है जो जोतने श्रौर बोने योग्य है । किन्तु वह बेकार पड़ी है । कुछ जमीन उन लोगों के हाथ में है जो न जोत सकते हैं न बो सकते हैं । मेरे कहने का श्रभिप्राय यह है कि जो जमीन बेकार घिरी हुई है श्रौर ऊसर है उस सब को फौरन भूमिहीन किसानों को दे देना चाहिये । सन् 1950 में उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन कानून बना । उस कानून के श्रनुसार पड़ती, बंजर, ऊसर जमीन जो जुताई के काम में श्रा सकती थी वह

सब गांव सभा के अधिकार में दे दी गई। कानून में यह प्रतिबन्ध होते हुए भी कि उपरोक्त भूमि का वितरण भूमिहीन और खेतिहर मजदूरों को देने में प्राथमिकता दी जायेगी, जमींदारी खत्म हुई, ग्राम पंचायतें आईं, फिर भी वह भूमि उन्हीं ताकतवर लोगों के हाथों में चली गई है जिनके पास पहले थी। आज यदि पूछा जाये कि कितने भूमिहीनों लोगों को ग्राम सभा की जमीन मिली तो उत्तर "ना" में मिलेगा। कहने का अभिप्राय यह है कि आज जनतन्त्र और समाजवादी युग में भी सरवाइवल आफ दि फिटेस्ट अर्थात् जिसकी लाठी उसकी भैंस की डारविन थिअरी ही अमल में लाई जा रही है। हमारी ग्रो मोर फूड की पालिसी कहां गयी ? किसानों को जब तक साधन उपलब्ध नहीं होते तब तक हमारी स्कीम सफल नहीं हो सकती और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते।

हमने सरकारी दफ्तरों में कृषि विशेषज्ञों की संख्या खूब बढ़ा ली है, किन्तु फिर भी कृषि उत्पादन में हानिकारक तत्वों को हटाने के लिए इन विशेषज्ञों ने अभी तक कोई उपाय नहीं निकाला है। कृषि की उन्नति करने के लिए अच्छी जमीन, खाद, पानी और उपयुक्त जलवायु की आवश्यकता है। सरकार ने इस समय दो संस्थाएं बनायी हैं, एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन और फूड कारपोरेशन आफ इण्डिया।

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं, मैं दूसरे मेम्बर को बुलाता हूं।

श्रीमती गंगा देवी : फूड कारपोरेशन किसानों से उनका अनाज उचित मूल्य देकर लेगा और उसको जनता को सही दामों पर बेचेगा। यह बहुत बड़ा कार्य कारपोरेशन को सौंपा गया है। मगर यह मेरी समझ में नहीं आता कि यह कारपोरेशन मद्रास में क्यों खोला गया, दिल्ली में क्यों नहीं खोला गया जहां खाद्य और कृषि मन्त्रालय के सभी दफ्तर हैं। यह कारपोरेशन यहां होना चाहिए था, या वह उत्तर प्रदेश में होता जहां किसानों की संख्या ज्यादा है और सभी प्रकार का खाद्य उत्पादन वहां मिलता है। मद्रास में यह कार्पोरेशन सफल नहीं हो सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर, आप बैठ जाएं। मिस्टर देशमुख।

Shri Shivaji Rao S. Deshmukh: Mr. Deputy-Speaker, Sir, while discussing these Demands for the Ministry of Food and Agriculture, I am conscious of the fact that what is uppermost in our mind now is not the Demands for Grants for this Ministry but what happens on the Kutch-Sind border. But I have a feeling that whatever happens there has something to do with what happens on our fields and factories. Therefore in that spirit we are all concerned with the Demands of this Ministry as well.

I have no doubt that Shri Subramaniam to agriculture is what fish is to water, but my fears are that he is more a Food Minister than an Agriculture Minister. Therefore, the moment we think of him as a Food Minister we think of a fish out of water and we wish that something must be done to see to it that the sturdy peasant and the sharp intellect which Shri Subramaniam undoubtedly commands go to the benefit of agriculture more than to the Department of Food.

While discussing these Demands my fears are that this annual ritual threatens to be an annual sermon on the funeral of agriculturists. I am very sorry to say this, but the agriculturists of today have got this feeling that whatever be their fate, the politicians, the administration and the party in power, who have always claimed that they stand by agriculture, when it comes to deeds, have lagged behind. We want that everything that is possible should be done to strengthen the hands of the agriculturists. We on this side of the House are prepared to go to any

[Shri Shivaji Rao S. Deshmukh]

length to strengthen the hon. Minister's hands to see to it that he does something useful for the agriculturists of India.

It has been stated that the White Paper which has been submitted as the policy decision of the Ministry of Food and Agriculture marks something like a step ahead. I had also intervened then saying that it had black things to say. I am sorry to say this, but it remains a fact that it has something to say about our policy decision on the pricing policy; it has something to say that they had established, what they call, a Jha Committee which was to recommend on an *ad hoc* basis what should be the price fixation of wheat as support price. What is the decision of this Jha Committee? It is that the support price of wheat should range from Rs. 40 to Rs. 50 per quintal. These rates prevailed in this country twelve years back. How can we now imagine ourselves that the rates which prevailed twelve years back in the field of agriculture can have any iota of supporting the prices? We are yet to believe that the price support and the pricing policy should evolve round a principle of remunerative prices. When it comes to paying lip-sympathy to the agriculturists, we rival with each other and claim that we are for remunerative prices for agriculturists. But when the agriculturists look at us as to what remunerative prices are, we have to show him twelve years back and say these constitute the support price.

We have also seen the unhappy spectacle that the prices of wheat in Punjab have fallen to the base, have even fallen beyond the so-called support prices and yet our Government, we find, is not in a mood to move. What for have they established the Food Trading Corporation? We expected that the Food Trading Corporation will support agriculturists on their procurement prices. Unfortunately, the Food Corporation is not in the picture in Punjab. It has its headquarters in Madras and from Madras we expect that they will support, leaving aside the distance, the agriculturists of Punjab. But we have seen that they are not in a mood to support the agriculturists of Punjab. Why this unhappy state of affairs has arisen is singularly because of our reluctance to abolish this zonal system. We have seen for two years the unhappy spectacle of artificially suppressing the foodgrains prices in Punjab, Uttar Pradesh and other surplus States and at the same time we have done nothing to see that the prices in deficit States do not rise beyond our reach. The result is the Government was reluctant and the reluctance of the Government has resulted in sugarcane area being diverted to gur and the result is that the sugarcane production which Government then boasted that it would rise to 30 lakh tons did not come up to even 25 lakh tons. How much had we gained? We would have gained four times in terms of foreign exchange had we exported sugar and had we not been pound foolish and penny wise then. So ours is the tragic story of failure after failure with no hope of success. If we are not to be drawn into that malady of wrong policy and if we are to take out agriculture and give it a push, give a shot in the arm, then nothing short of bold action will save our agriculture. If agricultural production increases to 82 million tons, we say our policy has given rise in agricultural production. If the production falls, then we seek nature's help and say that nature has been unkind to us and that is why the production has fallen. So, for all these 17 years, we have left agriculture to the nature. What sort of nature we have left it to? We have left it to the nature of our own self and not to the nature of mother's creation. We have year after year followed certain policies which we knew are not going

to pay us dividends. That the cultivators in the surplus States stand to lose and the cultivators in the deficit State do not stand to gain because in the deficit States also they have got, what they call, the monopoly procurement price, the monopoly procurement system. For instance, the agriculturist in Maharashtra gets for his jowar Rs. 42 as the maximum price, not the support price, and the agriculturist in some of the other adjoining jowar-producing States gets as the price of jowar something which is uncomparable to what the agriculturist gets in Maharashtra.

Why is this distinction between the agriculturist of one State and the agriculturist of another State? Why is this distinction between the agriculture of one State and the agriculture of another State when we claim that the subject agriculture and the pricing policies are definitely guided by the principles which emanate from Delhi? So, all the ills of agriculture today in India are due to our Central authority and those ills are precise because of our reluctance to enforce the Central authority or the federal authority. If today we have seen the unhappy spectacle of Centre's writ not working in the State, it is because the Centre does not want its writ to work in the State. If we want our writ to work in the State, we must see that our writ should have certain relations with India's existing conditions in agriculture today.

Now, for instance, coming to sugar, we had the unhappy spectacle of the Deputy Minister of Food stating that when the international price of sugar was 105 pounds per ton, we were not in a position to export sugar. Why were they not exporting sugar? It is because one year back, when this House demanded unanimously that Rs. 2 should be the minimum price per maund of sugarcane with 9 per cent recovery, And yet we have foolishly insisted on those policies. Those policies have been *ad hoc*. We have never thought how scientifically the cost of production could be worked out. We have established an Agricultural Prices Commission, and my congratulations are definitely due to the hon. Minister for having set up that commission. But after establishing that commission, Government have carefully seen to it that agriculturists are miles apart from the commission. It is just like having a butchers' commission on the prevention of cow-slaughter. I think that we should have seen to it that agriculturists are not only adequately represented but more than adequately represented on the Agricultural Prices Commission, because this commission has something to do with agriculure. When we say that we should also look to the consumers' interests, we should not do so at the expense of the agriculturists, but unfortunately that is what we are doing.

Take, for instance, the position in regard to cotton textiles. The Cotton Textile Advisory Board has taken a firm decision that whatever should be the ceiling price of cotton should be the floor price of cotton and the ceiling should be removed, but in the name of the consumer Government are reluctant to agree to this; they say that if this decision is put into effect it would mean that the consumer would have to pay more. But we have seen the spectable of our Finance Minister abolishing excise duty on coarse and medium cloth to the extent of 50 per cent in the hope that the prices of cloth will come down and that the consumer will benefit, but what has actually happened is that on the next day, in the next breath, another Minister increased the index price on the basis of which cotton prices were calculated, and the result was that the textile prices had gone up by 30 per cent instead of falling by even a paisa. I am afraid that all our economic policies are geard only to one interest, and that interest is to safeguard the interests of the private capitalists and private monopolists. If the hold of the private monopolists is to be broken, then we must take courage to see that the monopolists

[Shri Shivaji Rao. S. Deshmukh]

and the profiteers are not allowed to tamper with the problems of agriculture and that the agricultural problems are dealt with only by those who know something about agriculture, and by a Minister who is well conversant with it. If this could not be expected from the present Minister of Food and Agriculture, from who are we to expect this? The country looks to Shri C. Subramaniam for a lead in the field of agriculture, and the country is anxiously waiting to hear from his mouth what specific help he wants in the formulation of the Fourth Plan in this regard.

We see that 23 per cent of the funds are earmarked for agriculture in the Fourth Plan. When we know that 50 per cent of our income comes from agriculture and 50 per cent of our export earnings come from agriculture, we find at the same time that only a paltry sum of 23 per cent of the total outlay on the Plan has been earmarked for agriculture. If the hon. Minister is going to sit with tight lips and he is going to do nothing to increase this, then I would submit that that is a sorry spectable which this House would not like to see enacted.

Therefore, I would urge that the hon. Minister should do everything possible to see that agriculture makes a breakthrough, and that agriculture in India proceeds on the scientific lines on which we want it to proceed.

Shri Brij Raj Singh-Kotah: I am very grateful to you for giving me this chance to speak....

श्री यशपाल सिंह (कैराना): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस पर एक घंटे का समय श्रौर बढ़ा दिया जाय। इस पर समय बढ़ना चाहिए यह तमाम हाउस की राय है इसलिए इस पर एक घंटे का समय बढ़ाये जाने का प्रस्ताव मैं सदन के सामने पेश करता हूं।

Some hon. Members: We can sit till eight o' clock.

Shri S. C. Samanta (Tamluk): May I point out that there is no quorum in the House? How can the time be extended without quorum?

Mr. Deputy-Speaker: The count is being taken.

Shri Brij Raj Singh-Kotah: I am very grateful to you, for at last I have caught your eye, and tired as we all are, I am sure......

Shri S. C. Samanta: I am pressing for quorum.

Mr. Deputy-Speaker: The quorum has been challenged.

The hon. Member may now resume his seat.

The quorum bell is being rung—

There is no quorum. The House stands adjourned till 11 A.M. tomorrow.

19.26 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, April, 30, 1965/Vaisakha 10, 1887 (Saka).

GMGIPND—LS III—496(Ai) LSD—3-6-65—974.